



नंदिग्राम टाइम्स



Tuesday 9th, December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 223 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

वंदे मातरम् बहस में अनुराग ठाकुर का हमला — “कांग्रेस को चर्चा से डर है



लोकसभा में वंदे मातरम् पर चल रही बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि Indian National Congress के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा जानबूझकर सदन से गायब रहे ताकि वे इस बहस में भाग न लें। ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम् कोई साधारण गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र-भावना की “राष्ट्रीय प्रीत” है, जिससे कांग्रेस को “एलर्जी” होती है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस गाने की महत्ता समझी, वे देशभक्ति का मान रखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बहस से भाग रही है, क्योंकि वह इसके महत्व को स्वीकार नहीं करना चाहती।

इस बहस में बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम् देश की आत्मा है और इसे लेकर किसी तरह की राजनीति ठीक नहीं — वहीं कांग्रेस व उसके समर्थकों का आरोप है कि इस बहस का उपयोग आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।



NEWS DELHI | हम अपनी मां की इबादत नहीं करते...

हम अपनी मां की इबादत नहीं करते... वंदे मातरम् पर जोर-जबरदस्ती नहीं करे हुकूमत, ओवैसी ने क्यों कहा ये बात

नई दिल्ली | ऑल

इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि भारत में आजादी इसलिए आई कि हमने मुल्क और मज़हब को एक नहीं बनाया। उन्होंने लोकसभा में वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा, "हुकूमत इस पर जोर-जबर नहीं करे, अगर जबरदस्ती करेंगे तो यह संविधान के खिलाफ है।" ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने जंग-ए-आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज वे वतन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी खत्म की जाए।

वंदे मातरम् वफादारी का टेस्ट बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि भारत में आजादी इसलिए आई कि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। "



उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि "क्या वे वंदे मातरम् को वफादारी का 'टेस्ट' बनाना चाहते हैं?" उन्होंने वंदे मातरम् गाने या इसका उद्धोष करने के मुद्दे पर कहा, "हम अपनी मां की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। "

एआईएमआईएम सांसद ने वतन-परस्ती को मजहब में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए कहा, "वतन मेरा है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे...वफादारी का

सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। 'वंदे मातरम् का असली भाव समझना जरूरी समाजवादी पार्टी (सपा) की इकरा चौधरी ने कहा कि "हमें वंदे मातरम् के असली भाव को समझना जरूरी है।" उन्होंने यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक नदी का संकट नहीं, बल्कि किसान का संकट है। चौधरी ने कहा, "नमामि गंगे पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये गए, लेकिन जब पानी जहर हो जाएगा तो जल 'सुजलाम' कैसे होगा? किसान 'सुफलाम' कैसे होगा?"

उन्होंने सवाल किया कि क्या आज भारत में हवा 'मलयज शीतलाम्' है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो गया है। निर्दलीय सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "मैं जानना चाहता हूं कि आपने 53 साल राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं लगाया। आपकी संस्था और संगठन में कभी वंदे मातरम् गीत क्यों नहीं गाया गया? सपा की प्रिया सरोज ने कहा कि वह सरकार से अनुरोध करती हैं कि राष्ट्र प्रेम को दिखावे की चीज न बनाएं।

आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा: महायुती के 22 विधायक फडणवीस के करीबी, सत्ता परिवर्तन की आहट तेज



संवाददाता | NEWS AGENCY

नागपुर—महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार को उस समय हलचल मच गई जब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने महायुती सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 22 विधायक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के “पूरे प्रभाव में” हैं और किसी भी समय राजनीतिक पाला बदल सकते हैं। उनके अनुसार, ये विधायक सरकार के भीतर असंतोष के दौर में एक अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं।

नहीं है। ठाकरे का कहना था, “ये विधायक एक निर्देश पर खड़े हो जाते हैं, दूसरे पर बैठ जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी निष्ठा कहाँ झुक रही है।” इस दावे के बाद राज्य के राजनीतिक माहौल में खूबसूरत सुरू हो गई है। यह सवाल उठने लगा है कि यदि वास्तव में 22 विधायक पाला बदलते हैं, तो इसका सीधा असर सरकार की स्थिरता पर पड़ सकता है। ऐसे बदलाव से गठबंधन समीकरण ही नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीति भी पूरी तरह बदल सकती है।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन विधायकों को सरकारी निधि और अन्य लाभों का लालच दिखाकर नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समूह अब फडणवीस के हर राजनीतिक संकेत पर चल रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महायुती सरकार के भीतर सबकुछ सामान्य

सत्ताधारी पक्ष की ओर से ठाकरे के आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, परंतु राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान आगामी सत्ता समीकरणों की दिशा में एक संकेत है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।



केंद्र का स्पष्ट कहना — “झुगीवासियों का पुनर्वास राज्यों की जिम्मेदारी

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद में स्पष्ट कहा कि झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास केंद्र सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत दो वर्टिकल हैं — एक केंद्र द्वारा और एक राज्य द्वारा — और स्लम पुनर्वास वहीं राज्य सरकारों करेगी।

मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि केंद्र सिर्फ नीतियाँ व दिशा-निर्देश तय करता है; भूमि और कॉलोनाइजेशन राज्य का विषय है, इसलिए पुनर्वास की “बुनियादी जिम्मेदारी राज्यों” की होगी। इस प्रकार से केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ झुगीवासियों का पुनर्वास नहीं कर रहा, तो यह केन्द्र की नहीं — राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

आप 12 साल से और मैं मात्र 12 महीने से... वंदे मातरम् पर चर्चा के बीच प्रियंका गांधी की किस बात पर लोकसभा में मचा हंगामा



नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को वंदे मातरम् के 150 साल पूरा होने पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी ने की। चर्चा में कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान वंदे मातरम् पर हो रही चर्चा को लेकर ही सवाल उठाया। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं। प्रियंका ने पीएम मोदी पीएम मोदी के 12 साल की तुलना अपने 12 महीने के संसद सदस्य के अनुभव से की। 'आप 12 साल से...

मैं मात्र 12 महीने से' प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश के लिए जिए और देश की सेवा करते-करते दम तोड़ा। प्रियंका गांधी कहा कि अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इन्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कहा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 साल से सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ, फिर भी छोटी सी सलाह है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में चुनाव के दौरान पीएम की तरफ से 99 बार अपमान की सूची का जिक्र किया।

प्रियंका ने कहा कि आप पीएम का भाषण अच्छा

नेहरू जी से जितनी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की, जितनी भी गालियाँ देनी हैं, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना लीजिए। हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। इसके लिए आप जितने घंटे भी कहें उतनी चर्चा कर लेंगे लेकिन सदन का कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। सदन को जनता की समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए। प्रियंका की इस बात पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से विरोध व्यक्त किया गया। इसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

लेकिन तथ्यों में कमजोर प्रियंका गांधी ने सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के कण-कण में बसा है और देश की भावना से जुड़ा है। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें कला होती है कि कैसे जनता के सामने इसे रखा जाए। मैं नई हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार नहीं हूँ। इसलिए कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ।



टी-पार्टी का बहिष्कार: विपक्ष ने दिया विरोध, फडणवीस सरकार पर सवाल

नागपुर: 8 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे Maharashtra Winter Session (महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र) से पहले सत्ताधारी सरकार द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय-पान समारोह (टी-पार्टी) को विपक्षी दलों — Maha Vikas Aghadi (MVA) — ने बहिष्कार कर दिया है। Vijay Wadettiwar सहित विपक्षी नेताओं ने कहा कि दोनों सदनों में अब तक कोई Leader of Opposition (विरोधी पक्ष नेता, LoP) नियुक्त नहीं किया गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने टी-पार्टी में हिस्सा नहीं लिया।

विपक्ष का कहना है कि सिर्फ नेताओं को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजना — जबकि LoP पद रिक्त है — अस्वीकार्य है। इस बहिष्कार के पीछे भ्रष्टाचार, शेतकरी कर्ज माफी का अभाव, बढ़ती बेरोजगारी एवं ग्रामीण संकट को लेकर सरकार की नाकामी का गुस्सा भी है। लेकिन सरकार — प्रमुख रूप से Devendra

Fadnavis (मुख्यमंत्री) और Eknath Shinde (उप मुख्यमंत्री) Bhaskar Jadhav (शिवसेना- नेता) — ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि इस बहिष्कार से साबित होता है कि विपक्ष के पास “कोई ठोस मुद्दा नहीं है।” उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ “विरोधी पक्ष नेता की कुर्सी” पाने में फंसा हुआ है; जनता के असल मसलों — जैसे विकास, किसानों की समस्याएं — को इंडिजनोर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि LoP नियुक्ति का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के पास है — सरकार का नहीं — और यदि विरोधी दल कार्यवाही चाहते हों, तो संविधानिक प्रक्रिया अपनाएं। इस राजनीतिक टकराव के बीच शीतकालीन सत्र का माहौल गरम रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बहिष्कार और बातचीत-विवाद के बीच सत्र में किसान, बेरोजगारी, विकास और संविधानिक नियुक्तियों जैसे मसलों पर हंगामा होने की पूरी संभावना है।



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s unchanged.

महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही है उम्मीद — ज़मीन दस्तावेजों को डिजिटल मान्यता का नया अध्याय

संपादकीय... |

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ज़मीन संबंधी दस्तावेजों—जैसे 7/12 उतारा, 8-A, फेरफार विवरण व प्रॉपर्टी कार्ड—को डिजिटल स्वरूप में कानूनी मान्यता देने का निर्णय न केवल तकनीकी सुधार है, बल्कि राज्य की भूमि व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह कदम उस पारदर्शी व आधुनिक प्रशासनिक सोच की ओर संकेत करता है जो आने वाले वर्षों में भूमि प्रबंधन, निवेश और नागरिक सुविधा—all तीन क्षेत्रों को नई दिशा दे सकता है।

दशकों से भूमि दस्तावेजों को लेकर नागरिकों को भारी कागजी कार्यवाही, भ्रष्टाचार, बिचौलियों का दबाव और रिकॉर्ड में हेरफेर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। फर्जी 7/12 उतारे, दोहरे मालकी विवाद, गलत नोंदणी और गुम दस्तावेज—ये सारी समस्याएँ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आम थीं। लेकिन अब डिजिटल दस्तावेजों को वैधता मिलने से इन चुनौतियों पर सीधा प्रहार होगा। सरकार के अनुसार, डिजिटल दस्तावेज उतने ही प्रमाणिक माने जाएंगे जितने कागजी, और इन्हें अदालत, बैंक, सरकारी कार्यालय व रजिस्ट्रेशन विभाग में पूरा कानूनी दर्जा प्राप्त होगा।

इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ भूमि लेन-देन में पारदर्शिता के रूप में देखने को मिलेगा। निवेशक, किसान, खरीदार और बैंक अब बिना संदेह के डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जमीन की स्थिति, मालिकाना हक और ऋणयोग्यता की पुष्टि कर सकेंगे। इससे जमीन सौदों में होने वाली देरी कम होगी और राज्य में पूंजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। आज भारत में रियल-एस्टेट सेक्टर कई वर्षों से अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का यह कदम देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

किसानों के लिए भी यह सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अक्सर बैंकों से ऋण लेने में दस्तावेजों की सत्यता और उपलब्धता की समस्या आती थी। अब डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध सुरक्षित दस्तावेज किसानों को बिना बाधा के कृषि ऋण, अनुदान व फसल बीमा योजना तक पहुंच बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा, राजस्व रिकॉर्ड में होने वाले फेरफार को भी डिजिटल ट्रैकिंग से नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे जमीन विवादों की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है।

डिजिटलीकरण का एक और बड़ा लाभ यह है कि सभी दस्तावेज केंद्रीकृत डिजिटल लॉकर या सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा, चोरी या खो जाने की स्थिति में नागरिकों को नुकसान नहीं होगा। यह सुविधा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी है, जहाँ कागजी दस्तावेज अक्सर सुरक्षित नहीं रह पाते।

हालाँकि, इस नई व्यवस्था की सफलता पूरी तरह इस पर निर्भर करेगी कि सरकारी सर्वर, पोर्टल और रजिस्ट्रेशन सिस्टम कितने सुचारू रूप से चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता, साइबर सुरक्षा और रिकॉर्ड अपडेट की गति भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। यदि इन पहलुओं पर मजबूत तैयारी की गई, तो महाराष्ट्र देश में सबसे पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त भूमि-प्रबंधन प्रणाली वाला राज्य बन सकता है।

अंततः, महाराष्ट्र का यह निर्णय उम्मीद जगाता है—एक ऐसी उम्मीद जिसमें भ्रष्टाचार कम होगा, नागरिकों का समय बचेगा, किसानों को अधिकार मिलेगा और निवेशकों को भरोसा। यह कदम केवल डिजिटल दस्तावेजों को मान्यता देने का नहीं, बल्कि भूमि प्रशासन को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बदलने का प्रतीक है। राज्य की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और नागरिक सुविधा—तीनों को यह सुधार नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

BUSINESS NEWS | यूट्यूब के सीईओ नील मोहन अचानक सुर्खियों में क्यों?

Who is Neal Mohan: यूट्यूब के सीईओ नील मोहन अचानक सुर्खियों में क्यों? लखनऊ और संस्कृत भाषा से कनेक्शन जानिए

● NEWS AGENCY

नई दिल्ली: यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को 2025 के लिए टाइम सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी 'ध्यान भटकाने वाली मशीन' का पायलट बताया है। लेकिन, साथ ही यह भी कहा है कि वह 'आश्चर्यजनक रूप से शांत' हैं। वह कम बोलते हैं, सोच-समझकर फैसले लेते हैं और आसानी से विचलित नहीं होते। उन्हें खेल देखना, अपनी बेटियों के डॉस रिसेप्शन में जाना और सादी सफेद शर्ट पहनना पसंद है। बिल्कुल आम लोगों की तरह।

नील मोहन 2023 से यूट्यूब के सीईओ हैं। उन्होंने यह पद गूगल की संस्थापक कर्मचारियों में से एक सुसान वोजिकी के इस्तीफे के बाद संभाला था। इसके अलावा, वह स्टारबक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी हैं। नील मोहन 2008 में गूगल से जुड़े थे, जो यूट्यूब की पैरेंट कंपनी है। सीईओ बनने से पहले वह कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर थे।



लखनऊ के साथ कैसा कनेक्शन?

नील मोहन का जन्म इंडियाना के लैफायट में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अमेरिका में बिताया। लेकिन, 1985 में 12 साल की उम्र में वह अपने माता-पिता के साथ लखनऊ आ गए थे। उन्होंने 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। बाद में 2005 में उन्होंने इसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया, जहां वह अर्जे मिलर स्कॉलर थे।

स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस (GSB) में अर्जे मिलर स्कॉलर उन छात्रों को कहा जाता है जो एमबीए क्लास के टॉप 10% में आते हैं और जिन्होंने पढ़ाई में

शानदार प्रदर्शन किया हो। नील मोहन सिर्फ स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट ही नहीं हैं, बल्कि वह स्टैनफोर्ड GSB के एडवाइजरी काउंसिल और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदस्य भी हैं।

संस्कृत भाषा के बारे में कही यह बात संस्कृत भाषा से भी उनका दिलचस्प कनेक्शन रहा है। इसे सीखने के अपने अनुभव के बारे में नील मोहन ने कहा है, 'यह अविश्वसनीय रूप से ध्वन्यात्मक और नियमों पर आधारित है... यह मूल रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने जैसा था।' नील मोहन ने एक कुछ साल पहले स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस

में 'व्यू फ्रॉम द टॉप' नाम के एक कार्यक्रम में अपने बचपन और भारत लौटने के अपने माता-पिता के फैसले के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के मिडवेस्ट से आई स्कूल से ठीक पहले लखनऊ जैसे हलचल भरे शहर में जाना, न केवल उन्हें बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि ऐसे बदलावों के बीच आगे बढ़ने में भी मदद की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता, जो IIT-खड़गपुर से ग्रेजुएट थे, अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते थे। कैसे उन्होंने सिर्फ 25 डॉलर लेकर न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर कदम रखा था।

हाई स्कूल से ठीक पहले उनके माता-पिता ने भारत लौटने का फैसला किया। उस समय यह एक बहुत बड़ा नाटकीय बदलाव लगा। मोहन ने बताया था कि वह उस समय हिंदी बोल या लिख नहीं सकते थे। लेकिन, थोड़ा-बहुत समझ लेते थे क्योंकि उनके माता-पिता कभी-कभी घर में हिंदी बोलते थे। उनके जीवन के कुछ सबसे अच्छे दोस्त वे हैं जिनसे वह भारत में हाई स्कूल के दौरान मिले थे। उन्हें 9 साल की हिंदी और संस्कृत सीखनी पड़ी थी।

Indigo Crisis Deepens: इंडिगो के मुखिया हाजिर हों... डीजीसीए ने सीईओ और सीओओ को किया तलब, मामले ने पकड़ा तूल

Indigo Crisis Deepens: इंडिगो के मुखिया हाजिर हों...

NEWS AGENCY |

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एयरलाइन की उड़ानों में हो रही गड़बड़ी की जांच के लिए डीजीसीए की टीम बुधवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीईओ इसिद्रे पोरक्विरास को तलब कर सकती है। यह जानकारी सोमवार को एक सूत्र ने दी। यह चार सदस्यीय पैनल इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर हो रही रुकावटों के असली कारणों का पता लगाने के लिए गठित किया गया है। इस बीच एविएशन रेगुलेटर को इंडिगो का जवाब मिल गया है।

डीजीसीए के महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने 5 दिसंबर को इस पैनल की घोषणा की थी। इस पैनल में ज्वाइंट डीजी संजय ब्राह्मणे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित गुप्ता, सीनियर फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर कपिल मांगलिक और FOI लोकेश रामपाल शामिल हैं। पैनल का काम यह देखना है कि कहीं पायलटों के काम करने के घंटों और आराम के नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं।

क्या जांच कर रहा है पैनल?

यह पैनल इस बात की भी जांच करेगा कि इंडिगो ने पायलटों के ड्यूटी पीरियड और रेस्ट नॉर्म्स (काम के घंटे और आराम के नियम) को लागू करने की कितनी तैयारी की थी। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि क्या कंपनी ने संशोधित FDTL प्रावधानों (पायलटों के ड्यूटी और आराम से जुड़े बदले हुए नियम) का पालन किया है। पैनल उन कमियों का भी विश्लेषण करेगा जिन्हें खुद एयरलाइन ने स्वीकार किया है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि परिचालन में आई अस्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है और योजना बनाने में कहां गलती हुई।



एक सूत्र ने बताया, 'पैनल बुधवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और सीईओ इसिद्रे पोरक्वि रास को तलब कर सकता है। यह एयरलाइन की उड़ान सेवाओं में बड़े पैमाने पर आई रुकावटों की चल रही जांच का हिस्सा है।' यह जांच इंडिगो की उड़ानों में लगातार हो रही देरी और रद्द होने की घटनाओं के बाद की जा रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। डीजीसीए ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों।

WORLD NEWS | यूक्रेन, रूस से ज्यादा भ्रष्ट,

यूक्रेन, रूस से ज्यादा भ्रष्ट, जेलेंस्की युद्ध लंबा खींच रहे... ट्रंप के बेटे का बयान, बोले- अमेरिका चेकबुक वाला बेवकूफ नहीं बनेगा

वॉशिंगटन | रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने के लिए अमेरिका काफी कोशिश कर रहा है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं, दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लंदन में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्त्ज से मुलाकात करेंगे। वहीं, दूसरी तरफ जूनियर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति पर बड़े आरोप लगाए हैं।

जूनियर ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की जंग को इसलिए लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रूस के साथ लड़ाई खत्म हो गई तो वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वे वामपंथियों के लिए लगभग भगवान जैसे हैं, यूक्रेन, रूस से कहीं ज्यादा भ्रष्ट है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के दौरान कहा था कि अगर वे प्रेसिडेंट बनते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवा देंगे। ऐसे में जब जूनियर ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पीछे हट जाएंगे, तो जूनियर ट्रंप ने कहा कि शायद वे चले जाएंगे। ट्रंप राजनीति में सबसे



अप्रत्याशित लोगों में से एक हैं। ट्रंप जूनियर ने मोनाको का किया जिक्र,उन्होंने आगे कहा, "जब हम देखते हैं कि मोनाको में हर लाइसेंस प्लेट यूक्रेनी है, तो हम सभी

अफवाहें सुनते हैं कि क्या हो रहा है। अमीर भाग गए, और उन्होंने उन किसानों को छोड़ दिया जिन्हें वे इन लड़ाइयों में लड़ने के लिए मानते थे।

को छोड़ दिया जिन्हें वे इन लड़ाइयों में लड़ने के लिए मानते थे। रुकने का कोई कारण नहीं था क्योंकि जब तक पैसे की ट्रेन आ रही थी और वे चोरी कर रहे थे, कोई भी कुछ भी ऑडिट नहीं कर रहा था, इसलिए शांति बनाने का कोई कारण नहीं था। काजा कैलिस की भी जमकर आलोचना की

ट्रंप जूनियर ने ईयू के विदेश नीति के प्रमुख, काजा कैलिस की भी जमकर आलोचना की और कहा कि यूरोपियन बैन से कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि इससे सिर्फ रूसी तेल की कीमत बढ़ी है, जिसका इस्तेमाल मॉस्को यूक्रेन में अपनी लड़ाई के लिए फंड जुटाने में कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, "हम रूस के दिवालिया होने का इंतजार करेंगे; यह कोई योजना नहीं है।"

वेनेजुएला पर भी आरोप लगाया

वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध से हटकर कैरेबियन सागर में अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर जूनियर ट्रंप ने आरोप लगाया, "वेनेजुएला की ड्रग्स वाली नाव से अमेरिका में फेंटानिल आने का खतरा यूक्रेन या रूस में जो कुछ भी हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा साफ और मौजूदा खतरा है।"

पुतिन के भारत दौरे पर क्या बोला चीन, आपसी संबंधों की जमकर की तारीफ,

कहा- साथ काम करने को तैयार

बीजिंग: चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा पर सोमवार को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उसने तीनों देशों को 'ग्लोबल साउथ' का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा कि मजबूत त्रिपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के साथ-साथ उनके अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भी फायदेमंद हैं। चीन का यह बयान पुतिन की यात्रा के तीन दिन बाद आया है। पुतिन ने भारत यात्रा के दौरान 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा, "चीन, रूस और भारत न सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, बल्कि 'ग्लोबल साउथ' का अहम हिस्सा भी हैं।" यह पिछले हफ्ते पुतिन

की हाई-प्रोफाइल भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी बातचीत पर चीन की ओर से पहली प्रतिक्रिया है। गुओ ने कहा कि तीनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते न केवल उनके अपने हितों के अनुरूप हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए भी फायदेमंद हैं।

चीन, भारत और रूस के साथ काम करने को तैयार रूस के साथ चीन के मजबूत संबंधों के मद्देनजर बीजिंग की पुतिन की भारत यात्रा पर करीबी नजर थी। भारत यात्रा से पहले पुतिन की ओर से नई दिल्ली और बीजिंग के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़े सवाल पर गुओ ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रूस और भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा से पहले एक भारतीय समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा था, "भारत और चीन हमारे सबसे करीबी मित्र हैं। हम इस रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं।"



TTP या पाकिस्तान, किसी एक को चुने अफगानिस्तान...

TTP या पाकिस्तान, किसी एक को चुने अफगानिस्तान... CDF बनते ही तालिबान पर बरसे मुनीर, भारत के खिलाफ भी जहर उगला

इस्लामाबाद: आसिम मुनीर ने बतौर सीडीएफ अपने पहले ही भाषण में 'अटैक इज द बेस्ट डिफेंस' की नजीर पेश करने से बाज नहीं आए। अपने पड़ोसियों भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ फिर अनर्गल टिप्पणी की। सैन्य अफसरों के सामने दावा किया कि पाकिस्तान की काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीडीएफ नियुक्ति को लेकर सफाई भी दी।

मुनीर ने तालिबान के सामने दो विकल्प रखे,मुनीर ने सोमवार को नए सीडीएफ हेडक्वार्टर में तीनों सेनाओं को संबोधित करते हुए अपना गुबार निकाला। मीडिया आउटलेट 'जिओ' के अनुसार अफगानिस्तान से कहा कि अफगान तालिबान सरकार को या तो 'फितना अल-खवारी' या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है।

भारत के खिलाफ भी जहर उगला

वहीं भारत को भी याद किया। हर बार की तरह दोहराया

कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब "और भी तेज और कहीं ज्यादा सख्त" होगा। उन्होंने कहा, "अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी तेज और प्रचंड होगा।" देश के पहले सीडीएफ के तौर पर अपनी नियुक्ति के बाद जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) में उन्होंने कहा कि बढ़ते खतरों को देखते हुए, तीनों सेनाओं को एक यूनिफाइड सिस्टम के तहत काम करना चाहिए।

सीडीएफ पोस्ट को लेकर सफाई दी

सीडीएफ पद क्यों जरूरी है इसका जिक्र भी किया। बोले, "चुनौतियों के बढ़ते और बदलते नेचर को देखते हुए, एक यूनिफाइड ट्राई-सर्विसेज फ्रेमवर्क के तहत मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स को और मजबूत किया जाना चाहिए।" मुनीर ने कहा कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर बनाना इस दिशा में एक जरूरी कदम है। हर सर्विस ऑपरेशनल तैयारी के लिए अपनी पहचान बनाए रखेंगी, जबकि नया हेडक्वार्टर इंटर-सर्विस ऑपरेशन में तालमेल बिठाएगा।

जैश और लश्कर के | आतंकवादियों की पाकिस्तान में बड़ी बैठक,

जैश और लश्कर के आतंकवादियों की पाकिस्तान में बड़ी बैठक, जिस बहावलपुर को भारत ने मिट्टी में मिलाया, वहीं की हमले की प्लानिंग



इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला बहालपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। यह वही बहावलपुर है, जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन, खबर है कि एक बार फिर पाकिस्तान के दो प्रमुख आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने बहावलपुर में संयुक्त बैठक की है। इस बैठक में भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों पर चर्चा हुई है। इन दोनों आतंकी समूहों के एक होने और बहावलपुर में बड़ी बैठक करने से भारत की चिंता बढ़ गई है।

लश्कर और जैश की संयुक्त बैठक एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बैठक की तस्वीरें भी आई हैं। इन तस्वीरों में लश्कर के डिग्री चीफ सैफुल्लाह कसूरी जैश कमांडरों के साथ दिखाई दिया है। ये तस्वीरें इंटेलिजेंस कम्युनिटी की उन चैतावनियों को दिखाती हैं जिनमें लश्कर-ए-तैयब और जैश-ए-मोहम्मद एक साथ काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इनकी यह बैठक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर हुई है।

रावलकोट में नया टेरर लॉन्च पैड तैयार रिपोर्ट में इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में टेरर लॉन्च पैड फिर से बनाए जा रहे हैं। इस आतंकी अड्डे को भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेस्तनाबूद किया था। पिछले महीने भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जैश-ए-मोहम्मद लाल किले पर कार बम विस्फोट के बाद एक और फिदायीन स्कॉड तैयार कर रहा है, ताकि भारत में नया हमला किया जा सके। जैश इसके लिए भारी मात्रा में फंड भी जमा कर रहा है।

NEWS AGENCY

मॉस्को: रूसी संसद ने भारत के साथ रैसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (रेलोस) समझौते को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ इस समझौते से भारत की समुद्री पहुंच में जबरदस्त इजाफा होने वाले है। इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय नौसेना को होगा। अब भारतीय नौसेना हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक महासागर तक रूसी नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। इतना ही नहीं, इन नौसैनिक अड्डों से भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे लंबी दूरी के समुद्री मिशन को अंजाम देने में काफी सहूलियतें मिलेंगी। रूसी संसद ड्यूमा ने इस समझौते को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले मंजूरी दी थी, हालांकि इस पर दोनों देशों के बीच 18 फरवरी, 2025 को मॉस्को में साइन किया गया था।

भारतीय रणनीति का बड़ा हिस्सा है यह समझौता रूस के साथ रेलोस समझौता भारत की बड़ी रणनीतिक योजना का हिस्सा है जो 2015 में SAGAR सिद्धांत के साथ शुरू हुई थी। इस सिद्धांत के तहत भारत ने पहली बार एक ज्यादा बड़ी समुद्री भूमिका तय की थी। इसके बाद इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI), इंडियन ओशन नेवल सिंजोयियम (IONS) और इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) जैसी पहल की गई।



भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ अपना पहला लॉजिस्टिक्स पैक्ट, LEMOA, साइन किया था और तब से जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान और फिलीपींस जैसे पार्टनर्स के साथ ऐसे समझौते को लेकर बातचीत जारी है। भारत-रूस संबंधों में नया आयाम पुतिन के भारत दौरे से पहले इस समझौते को मंजूरी मिलना रूस का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। यह कदम भारत-रूस मिलिट्री कोऑपरेशन की ऑपरेशनल नींव को मजबूत करता है और दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए नए कमिटमेंट को दिखाता है। रेलोस एक बाइलेटरल लॉजिस्टिक्स पैक्ट है जो मिलिट्री यूनिट्स को भेजने, पोर्ट कॉल करने,

एयरस्पेस और एयरफील्ड का इस्तेमाल करने और मिशनस, जॉइंट एक्सरसाइज और ह्यूमैनिटेरियन या डिजास्टर से जुड़े ऑपरेशन्स के दौरान लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने की प्रक्रिया को बताता है।

रेलोस समझौते से क्या होगा यह समझौता भारतीय और रूसी सेनाओं को जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग मिशन, मानवीय ऑपरेशन और आपदा राहत के दौरान ज्यादा अच्छे से काम करने में मदद करता है। इससे रिफ्यूलिंग, रीप्लेनिशमेंट, मेंटेनेंस और दूसरी लॉजिस्टिक ज़रूरतों को आसान बनाया जा सकेगा। रेलोस, व्लादिवोस्तोक से मरमंस्क तक उत्तरी समुद्री रास्ते पर रूसी नेवल पोर्ट तक पहुंच देकर, खासकर भारतीय नौसेना के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच को काफी बढ़ाता है।

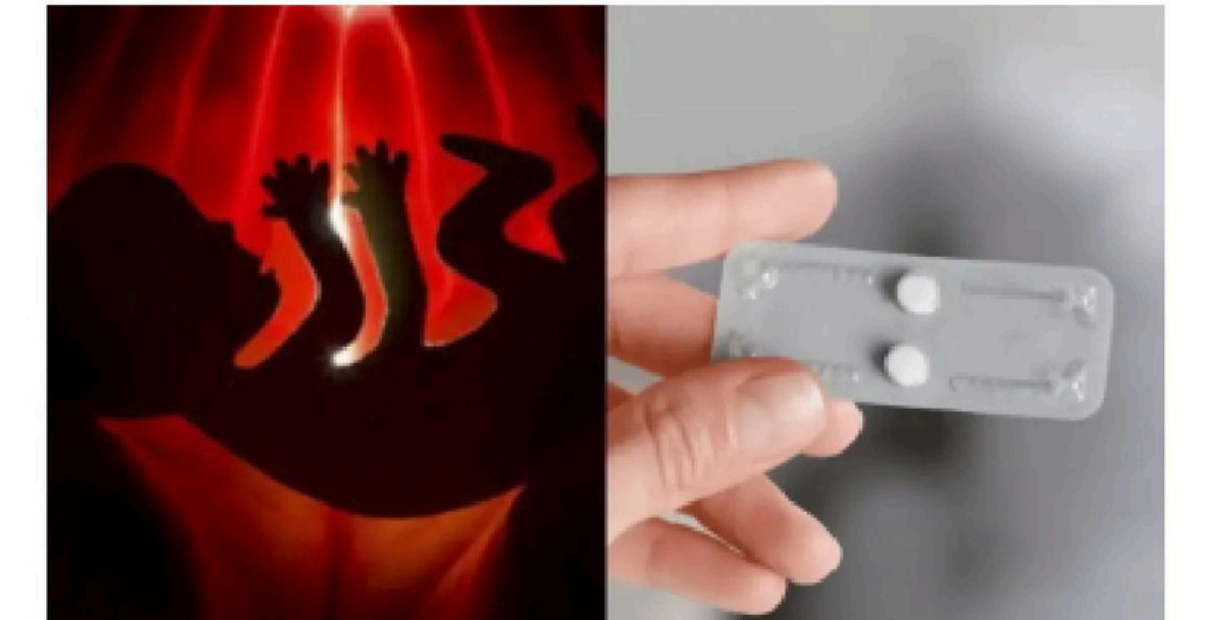


नंदिग्राम टाइम्स



Tue 9th, December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 223 | ● पृष्ठ 04 | ● RNI-MAHHIN/2016/69743 | ● www.nandigramtimes.com

जालना में अवैध गर्भपात दवाओं की खुली बिक्री — स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर



जालना — मेडिकल स्टोर्स पर बिना डॉक्टर की पर्ची गर्भपात की दवाओं की खुलेआम बिक्री से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। प्रतिबंधित एमटीपी किट एवं गर्भपात गोलियाँ आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे अवैध गर्भपात और भ्रूण हत्या का खतरा बढ़ गया है। नियमन की कमी का फायदा उठाकर कुछ मेडिकल स्टोर संचालक शेड्यूल-N दवाओं का अवैध व्यापार कर रहे हैं। स्वास्थ्य व औषधि प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि बिना पर्ची दवाएं पाई गईं, तो संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

हदगांव में भीषण सड़क हादसा — अंतिम संस्कार से लौट रहे ऑटो को तेज रफ्तार कार ने पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत, तीन गंभीर

हदगांव ((शेख खय्यूम सोनारीकर)) | — सोमवार, 8 दिसंबर की शाम करीब पाँच बजे तुळजापुर-नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर बावणी फाटा और बरडशेवाला के बीच स्थित शिवगंगा पेट्रोल पंप के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। चिंचगाव गांव में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार से लौट रहे लोगों से भरे ऑटो को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।



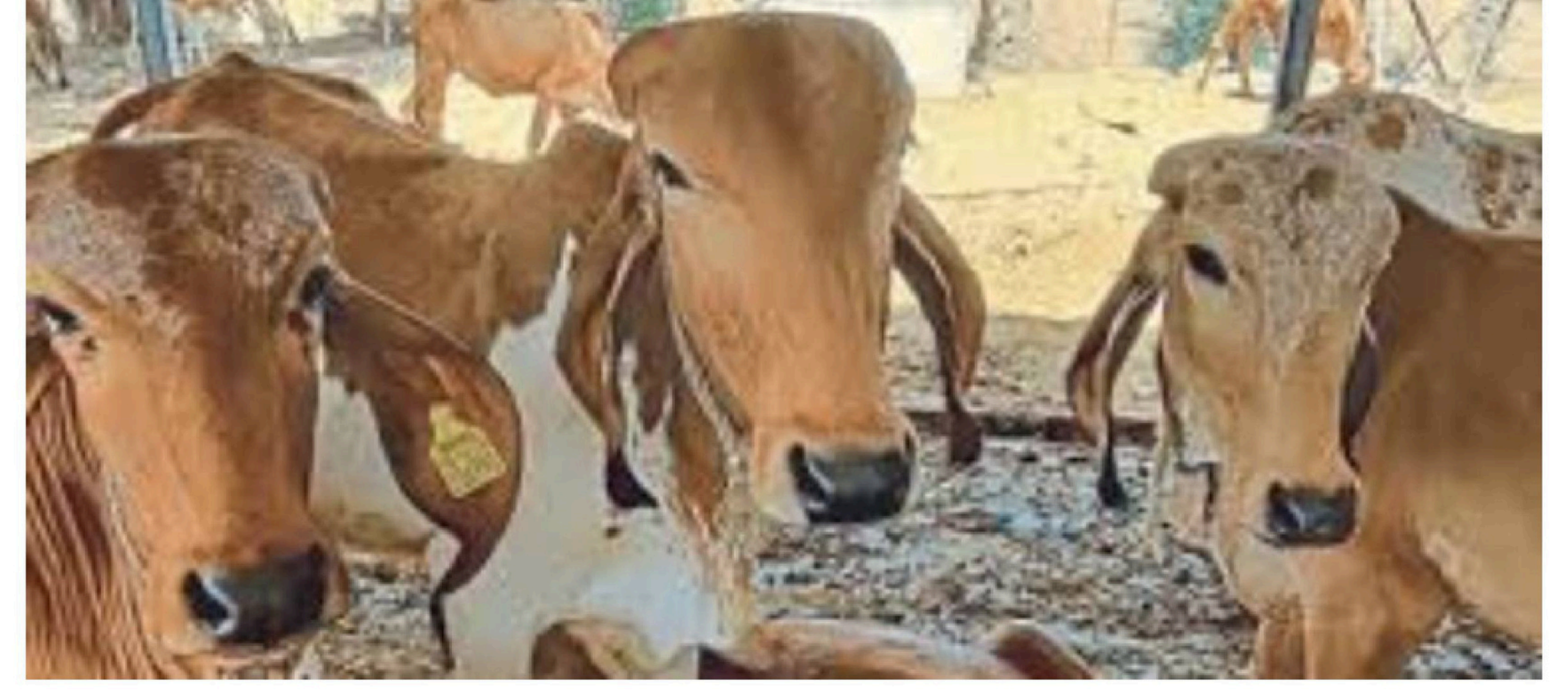
इस दुर्घटना में अशोक काशीनाथ नेवरकर (55), निवासी सोनारी, की मौत पर ही मौत हो गई।

जबकि तीन महिलाएँ — शोभाबाई उत्तम शेलके, द्रोपदाबाई रामराव पाटे और सिंधुबाई नारायण हुंबे — गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को तुरंत

मनाठा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक विलास चवळी, बिट जमादार अशोक दांडे और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजने के साथ आगे की कार्रवाई शुरू की।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस राष्ट्रीय महामार्ग पर दुर्घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। मार्ग पर दिशा-सूचक बोर्ड, आपातकालीन सुविधाएँ और निगरानी कर्मियों की कमी के कारण यह सड़क बेहद खतरनाक बन चुकी है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है।

नांदेड़ में अवैध गोवंश तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार



संवाददाता |

नांदेड़ — जिले की स्थानीय गुन्हे शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। आलू-कांदा मार्केट के पास गाडेगांव रोड पर छापामारकर पुलिस ने बोलरो पिकअप (MH-02-FG-0978) और 05 गोवंशीय पशुओं सहित कुल ₹9,25,000 मूल्य का माल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। यह संपूर्ण ऑपरेशन पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अर्चना पाटिल और

अपर पुलिस अधीक्षक सूरज गुरव के मार्गदर्शनावाली चलाया गया। निरीक्षक उदय खंडेराय और उनकी टीम ने मौके पर तत्परता से छापामारकर कार्रवाई को सफल बनाया।

पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध गोवंश तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि ऐसे गैरकानूनी कामों पर अब सख्त निगरानी और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

सरस्सम गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप —

पीड़ित ने ZP अधिकारी से की कार्रवाई की मांग

संवाददाता-(शेख खय्यूम सोनारीकर)

हिमायतनगर। हिमायतनगर तालुका के सरस्सम गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गांव के निवासी शैलेश रामराव मोतेवार ने जिला परिषद नांदेड़ के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी को शिकायत पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि उनके आवास के पास स्थित सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, अवैध निर्माण के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे उनके परिवार की

आवाजाही प्रभावित हो रही है। साथ ही, उनके बच्चों की सुरक्षा, घर की गोपनीयता तथा आसपास के वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति लगातार ईंट-पत्थर डालकर दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मोतेवार ने प्रशासन से इस अवैध निर्माण को तुरंत रोकने, कब्जा हटाने और भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।



नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रेमी की हत्या किए जाने पर प्रेमिका ने शव के साथ शादी करके चौंका दिया था। सक्षम ताटे नाम के युवक से बेइंतहा प्यार करने वाली आंचल ने अब इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है। सक्षम ताटे को आंचल के पिता और भाई ने मार डाला था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑनर किलिंग की इस घटना की वजह इंटर-कास्ट को माना गया था।

महाराष्ट्र: प्रेमी के शव से क्यों की शादी? सक्षम की हत्या के बाद प्रेमिका आंचल ने बताई वजह

इस मामले में तब ट्रिस्ट आया था जब आंचल ने कहा था कि सक्षम की हत्या में पुलिसवाले भी शामिल हैं। आंचल ने कहा था कि सक्षम की हत्या के मेरे भाई को पुलिस ने उकसाया था। अब आंचल ने सक्षम की मौत के बाद शव से शादी करने और उसकी नाम का सिंदूर मांग में भरने की वजह का खुलासा किया है।

मौत के बाद क्यों की शादी? सक्षम ताटे की हत्या के बाद गहरे दुख से उबर रही आंचल ममीदार ने अब मौत के बाद शादी की वजह का खुलासा किया है। आंचल का कहना है कि मैं अपने परिवार को नहीं जीतने देना चाहती हूँ। आंचल के 19 साल के पार्टनर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में

उसके घर से कुछ ही मीटर दूर गोली मार दी गई थी। नांदेड़ में यह घटना 28 नवंबर की सुबह हुई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इंटर-कास्ट रिलेशनशिप के भयानक अंत पर हर कोई अचंभित है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर ने इस घटना की निंदा की है। पुलिस ने इस घटना में आंचल में पिता और दो भाईयों को अरेस्ट किया था। सक्षम की हत्या के बाद आंचल ने घर छोड़ दिया था। वह सक्षम के घर में रह रही है। आंचल का कहना है उसके परिवार ने उसे धोखा दिया। सक्षम की हत्या के लिए भाई और पिता को मौत की सजा मिलनी चाहिए।

शालार्थ घोटाले की परतें गहराई: संभाजीनगर SIT को जांच के लिए चार माह का अतिरिक्त समय

संवाददाता

छत्रपति संभाजीनगर : राज्य की 'शालार्थ प्रणाली' में सामने आए बड़े घोटाले की जांच अब और चार महीने तक बढ़ा दी गई है। अपात्र तथा शिक्षकेतर व्यक्तियों के नाम प्रणाली में जोड़कर उन्हें वेतन जारी किए जाने के मामले ने इतना व्यापक रूप ले लिया है कि विशेष जांच दल (SIT) को निर्धारित समयसीमा में जांच पूरी करना संभव नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि विभिन्न जिलों से लगातार नई शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके चलते जांच की दिशा और दायरा दोनों बढ़ गए हैं।

नागपुर, नाशिक, जलगांव, बीड, लातूर, मुंबई समेत कई जिलों से प्राप्त शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि शालार्थ प्रणाली में ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए, जिनकी न तो पात्रता स्पष्ट है और न ही कुछ मामलों में उनका अस्तित्व ही सिद्ध होता है।



इन फर्जी नामों के आधार पर महीनों तक वेतन जारी किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का संभावित नुकसान हुआ है। विभागीय आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक जांच में कई नए पहलू सामने आए हैं। अब तक की पूछताछ और दस्तावेजों की समीक्षा में संदेहास्पद प्रक्रियाओं का बड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के अनुसार स्कूलवार रिकॉर्ड

की जांच, संदिग्ध कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल, संबंधित अधिकारियों से पूछताछ और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण चरण अभी पूरे होने बाकी हैं। सरकार का कहना है कि घोटाले की गंभीरता और बढ़ती शिकायतों को देखते हुए SIT को अतिरिक्त चार माह का समय देना अनिवार्य था, ताकि जांच व्यापक, निष्पक्ष और ठोस निष्कर्ष पर आधारित हो सके।

बाबरी के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो मैं बंगाल आउंगी और...हुमायूं कबीर के खिलाफ नवनीत राणा ने खोला मोर्चा

नागपुर | पश्चिम बंगाल में

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की फायरब्रांड नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने बड़ा बयान दिया है। राणा ने कहा कि बाबरी की नींव जो लगाई है। उसे जल्द कारसेवा कर उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम भागीरथ धाम किया जाएगा और गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। राणा ने कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं बंगाल आउंगी और उसे गिरा दूंगी।

अमरावती से ईंट जाएगी मुर्शिदाबाद अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने मुर्शिदाबाद जिले का नाम भागीरथ धाम करने की मांग करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाए जाने वाले



राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र के अमरावती जिले से रामनामी ईंट जाएगी। गौरतलब हो कि ठंडी के मौसम में पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा चढ़ है। वहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद बनाने की आधारशिला रखी थी। इस पर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया, लेकिन इस मामले को

हिंदू संगठनों ने उठा लिया है। वहां के बहरामपुर में अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही नया मंदिर बनाने की आधारशिला रखी। भागीरथ धाम नाम की वजह? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की खबर के बाद नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान भी दिया था कि अगर, बाबरी के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो मैं बंगाल आउंगी और उसे गिरा दूंगी।

अब वह राम नाम लिखे ईंट लेकर मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि राम नाम लिखी गई दो टुक वे मुर्शिदाबाद भेजेंगी और खुद भी वहां जाएंगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुर्शिदाबाद का नाम भागीरथ धाम किया जाएगा और गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है इसलिए उसे भागीरथ धाम भी कहा जाता है। नवनीत राणा ने इसी आधार पर मुर्शिदाबाद का नामकरण भागीरथ धाम करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने विधायकी से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। पहले टीएमसी ने निकाले जाने पर कबीर ने इस्तीफे की बात कही थी।